डिमांड बढ़ने से मिलों ने 3.5 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट के सौदे किए

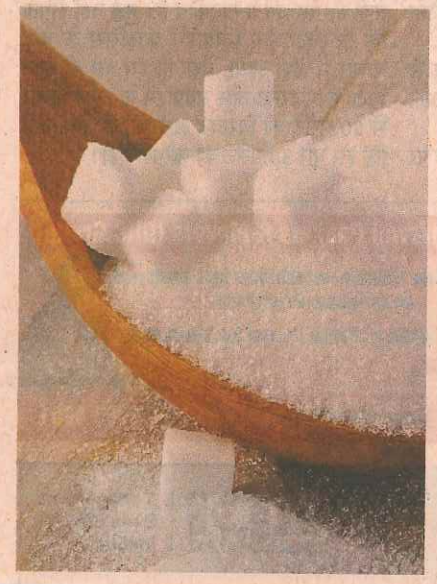

[जयश्री भोसले | पुणे]

भारतीय चीनी की अच्छी डिमांड से एक्सपोर्ट में तेजी आ रही है। देश की चीनी मिलों ने 3.5 लाख टन के एक्सपोर्ट के लिए डील्स साइन की हैं। चीनी का पूरी क्षमता के साथ उत्पादन और डिस्पैच दिवाली के बाद ही शुरू होगा।

ऑल इंडिया शुगर ट्रेडर्स एसोसिएशन (AISTA) के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी ने बताया, 'चीनी की डिमांड अधिक होने के कारण अभी तक लगभग 3.5 लाख टन चीनी के लिए एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं।' कच्ची चीनी की कीमतों में और बढ़ोतरी की वजह से मिलों को कच्ची चीनी के लिए 1,950 रुपये प्रति क्विंटल और व्हाइट शुगर के लिए 2,100 रुपये प्रति क्विंटल का प्राइस मिल रहा है।

महाराष्ट्र सरकार ने चीनी का उत्पादन शुरू करने के लिए मिलों को क्रशिंग लाइसेंस जारी करना आरंभ कर दिया है। पुणे और अहमदनगर की कुछ मिलें इस सप्ताह पेराई शुरू करेंगी। हालांकि, राज्य के चीनी उत्पादन में लगभग एक-चौथाई हिस्सेदारी रखने वाले कोल्हापुर सांगली क्षेत्र में पेराई अगले महीने ही शुरू होगी।

कोल्हापुर में शुगर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट विजय औतादे ने बताया, 'कुछ मिलों को छोड़कर कोल्हापुर क्षेत्र की अधिकतर चीनी मिलें दिवाली के बाद ही पेराई शुरू करेंगी क्योंकि किसानों के संगठन अपनी मांगें पूरी होने तक मिलों को कामकाज शुरू नहीं करने देंगे।'

- **मिलों को** कच्ची चीनी के लिए 1,950 रुपये और व्हाइट शुगर के लिए 2,100 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है
- **महाराष्ट्र सरकार** ने चीनी का उत्पादन शुरू करने के लिए मिलों को क्रशिंग लाइसेंस जारी करना आरंभ कर दिया है, पुणे और अहमदनगर की कुछ मिलें इस सप्ताह पेराई शुरू करेंगी
- **ट्रेडर्स और** एक्सपोर्ट फर्में 2018-19 में केंद्र सरकार की ओर से 50 लाख टन चीनी के एक्सपोर्ट के लिए दिए जा रहे इंसेंटिव्स का मिलों को फायदा दिलाने की कोशिशें कर रहे हैं

मराठवाड़ा की मिलों को चीनी का उत्पादन शुरू करने के लिए एक पखवाड़े तक और इंतजार करना होगा। वेस्ट इंडिया शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन बी बी थॉम्ब्रे ने कहा, 'कटाई और परिवहन से जुड़े श्रमिकों के संगठन मजदूरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं और इस मुद्दे का समाधान होने के बाद ही मराठवाड़ा की चीनी मिलें पेराई शुरू कर सकेंगी।' महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे गन्ने की कटाई करने वाले श्रमिकों की नेता हैं और अगले वर्ष राज्य में चुनाव के मद्देनजर पंकजा और अन्य नेता इन मुद्दों पर अपनी ताकत दिखा सकते हैं।

कोल्हापुर में चीनी मिलें राजू शेट्टी की अगुवाई वाले स्वाभिमानी शेतकारी संगठन से संकेत मिलने का इंतजार कर रही हैं। गन्ने की कीमत और भुगतान की योजना पर मोलभाव न करने की स्थिति में संगठन प्रदर्शन कर सकता है।

ट्रेडर्स और एक्सपोर्ट फर्में 2018-19 में केंद्र सरकार की ओर से 50 लाख टन चीनी के एक्सपोर्ट के लिए दिए जा रहे इंसेंटिव्स का मिलों को फायदा दिलाने की कोशिशें कर रहे हैं।

महाराष्ट्र की शुगर इंडस्ट्री के नेता शरद पवार ने हाल ही में चीनी मिलों के साथ बातचीत की थी। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव शुगर मिल्स फेडरेशन, AISTA और ट्रेडर्स सोमवार को मुंबई में मिल मालिकों को इसके बारे में जानकारी देंगे। शुगर इंडस्ट्री को केंद्र सरकार की स्कीम के तहत 40 लाख टन से अधिक चीनी का एक्सपोर्ट करने की उम्मीद है।

Economic Times
22/10/2018